



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

C. Kaur
1.1.85

सं० 521]
No. 521]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 22, 1984/अश्विन 30, 1906
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 22, 1984/ASVINA 30, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय
(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 22 अक्तूबर, 1984

स्पष्टीकरण ज्ञापन

का आ 804(अ) —भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय ने भारत के राजपत्र के असाधारण संस्करण भाग 2, खण्ड 3(2) में 9 मार्च, 1983 को प्रकाशित अधिसूचना सं. 168-अ के माध्यम से तोषण निधि स्कीम, 1982 को संशोधित किया। संशोधित स्कीम को तोषण निधि स्कीम के प्रभावी होने की तारीख 1 अक्तूबर, 1982 से लागू की गई।

2 यह संशोधन पहले क्लेम इन्क्वायरी आफिसर को एक राह की अवधि के अवसान के बाद भी क्लेम सम्बन्धी आवेदन पत्र स्वीकार करने के लिए शक्ति प्रदान करने के संबंध में था। तोषण निधि स्कीम ने, गंभीर चोट लगने वाले व्यक्तियों या टक्कर मारकर भाग जाने के मामलों में मृत व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करने की व्यवस्था की थी। इसमें यह शर्त थी कि क्लेम सम्बन्धी आवेदन पत्र टक्कर-मारकर भागने वाली

मोटर दुर्घटनाओं की तारीख से एक माह के अन्दर प्रस्तुत किए जाय। चूंकि तोषण निधि स्कीम की शुरुआत एक नई अवधारणा थी, इसलिए राज्य-सघ क्षेत्र प्रशासनों में विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को ऐसे क्लेम स्वीकार करने के लिए अपने आपको तैयार संगठित करने में कुछ समय लगा। पुनः उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की उपलब्धता का प्रचार करने के लिए विभिन्न उपाय किए जाने के बावजूद भी यह पाया गया कि जनसाधारण को सामाजिक रूप से इस लाभकारी उपाय के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए यह जरूरी समझा गया कि प्रारम्भिक चरण में जो व्यक्ति सूचना के अभाव में क्लेम सम्बन्धी आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सके, उनसे क्लेम आवेदन पत्र प्राप्त करने की समय सीमा बढ़ाई जाए। इस संशोधन का उद्देश्य यह था कि सभी मामलों में स्कीम के क्रियान्वयन की तारीख से वित्तीय राहत का लाभ प्रदान किया जा सके। इसलिए अधिसूचना सं. 168-अ में तोषण निधि (संशोधन) स्कीम, 1983 को 1 अक्तूबर, 1982 से प्रभावी किया गया था। इस अधिसूचना को पिछली तारीख से प्रभावी करने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

[फाइल सं. टी जी एम-28/82]
गोविन्द जी मिश्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

New Delhi, the 22nd Oct. 1984.

EXPLANATORY MEMORANDUM

S.O. 804(E).—The Government of India in the Ministry of Shipping and Transport amended the Solatium Fund Scheme, 1982 vide Notification No. 168-E, published in the Gazette of India, Extraordinary, on 9th March, 1983 in Part II Section 3(ii). The provisions of the amended scheme were brought into force retrospectively with effect from the 1st October 1982, the date on which the Solatium Fund Scheme came into force.

2. The amendment primarily related to empowering the Claims Enquiry Officer to entertain claim application even after the expiry of the period of one month. The Solatium Fund Scheme had made a provision for providing immediate financial relief to the victim of grievous hurt or the heirs of the deceased involved in hit-and-run cases. It was stipula-

ted that the claim applications be filed within one month of such hit-and-run motor accidents. Since the introduction of Solatium Fund Scheme was entirely a new concept, various implementing agencies in the State/Union Territory Administrations took some time to organize themselves to entertain such claims. Further despite various steps to publicise the availability of facilities being made available, it was observed that the public was not fully aware of this socially beneficial measure. It was therefore, considered necessary that in the initial stage, the time-limit for entertaining receipt of Claim applications from those who could not file their claims due to lack of information may be extended. The intention behind this amendment was that the benefit of financial relief could be made available to all cases from the date of implementation of the Scheme itself. The notification number 168-E the Solatium Fund (Amendment) Scheme, 1983 was therefore given retrospective effect from the 1st October, 1982. Giving of retrospective effect has not affected anyone pre-judicially.

[File No. TGM-28/82].

G. J. MISRA, Joint Secy.